भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1019

उत्तर देने की तारीखः 09.03.201**7**

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शुल्क माफी चाहने वाले छात्रों की वित्तीय स्थिति

1019. श्री ए॰ के॰ सेल्वाराजः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या इस वर्ष जनवरी से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कम आय वाले परिवारों से आने वाले छात्रों को मदद करने के उद्देश्य से बनी योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए शुल्क माफी चाहने वाले छात्रों की आर्थिक स्थिति का सत्यापन करने की शुरुआत करेंगे**;

**(ख) यदि हां**, **तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;

**(ग) क्या यह कदम अप्रैल**, **2016 से शिक्षण शुल्क को 90000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किए जाने के बाद शिक्षण शुल्क का भुगतान करने से छूट चाहने वाले स्नातक पूर्व छात्रों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी होने के परिणामस्वरूप उक्त योजना की समीक्षा करने की योजना का भाग है**; **और**

**(घ) यदि हां**, **तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय)

(क) से (घ): जी, हां। आईआईटी परिषद् ने निर्णय लिया है कि जिन छात्रों ने प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए से कम की पारिवारिक आय के कारण शुल्क में छूट की मांग की है, उनके आय प्रमाण-पत्रों की जांच की जाएगी। शुल्क प्रणाली में किसी भी प्रकार का संशोधन आईआईटी परिषद् की अगली बैठक के पश्चात् किया जाएगा।

\*\*\*\*\*